



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 3, March 2022

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.569

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक रणनीति

Dr. Sudhir Singh

Assistant Professor in Political Science, Government PG College, Rajakheda, Dhauipur, India

सारांश

भारत का ध्रुवीकरण करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को अपने इर्द-गिर्द समेट दिया था. हालांकि उनके सामने चुनौतियां भी थीं. एंटी इनकंबेन्सी का फैक्टर था.

बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ चुकी थी, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी थी और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई थी. कई भारतीयों को नोटबंदी से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था. हालांकि नोटबंदी के बारे में सरकार का दावा कर रही थी इससे घोषित संपत्ति को बाहर निकलवाने में कामयाबी मिलेगी. इसके अलावा जीएसटी को लेकर भी कई शिकायतें थीं. लेकिन चुनावी नतीजों से साफ़ है कि आम लोग इन सबके लिए मोदी को ज़िम्मेदार नहीं मानते. नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में लगातार कहते आए हैं कि उन्हें 60 साल की अव्यवस्था को सुधारने के लिए पांच साल से ज़्यादा का वक़्त चाहिए. आम लोगों ने उन्हें ज़्यादा वक़्त देने का फ़ैसला लिया है.

कई लोग मोदी को अपनी समस्याओं को हल करने वाला मसीहा भी मानते हैं. दिल्ली के थिंक टैंक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ़ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) के एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी के हर तीसरे मतदाता का कहना है कि अगर मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होते तो वे अपना वोट किसी दूसरी पार्टी को देते. दरअसल, इंदिरा गांधी के बाद मोदी भारत के सबसे लोकप्रिय नेता साबित हुए हैं. वाशिंगटन के कारनेजी इंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के सीनियर फेलो मिलन वैष्णव कहते हैं, "इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह वोट बीजेपी से ज़्यादा मोदी के लिए है. यह चुनाव सबकुछ छोड़कर मोदी के नेतृत्व के बारे में था."

17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदरदास मोदी 26 मई 2014 से देश के 14वें प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हैं. सन् 2019 में हुए भारत की लोकसभा के चुनाव एकदम विपरीत शैली में लड़े गए थे. नरेंद्र दामोदरदास मोदी के नेतृत्व में भाजपा-एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) पूरी तरह व्यक्तित्व आधारित शैली में चुनाव लड़ रहा था. "मोदी है तो मुमकिन है" का डंका पीटा जा रहा था. दूसरी ओर एक भ्रमित से विपक्ष का मानना था कि भारत में चुनाव मुख्यतः राज्यों में लड़े जाते हैं, जिनमें राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दे भी ख़ासे महत्वपूर्ण होते हैं. साथ ही वर्तमान सांसद व विधायकों के खिलाफ असंतोष बहुत सारे समीकरण गड़बड़ा देता है. चूंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी व एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था, सो निश्चित ही उस समय उन्हीं के सांसदों की अधिकता थी. विपक्ष को लग रहा था कि इनके खिलाफ असंतोष को भुनाया जा सकेगा.

परिचय

एक तरह से, लगातार दूसरी बार शानदार जीत हासिल करने वाले मोदी की तुलना 1980 के दशक लोकप्रिय अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन से की जा सकती है, जिन्हें उस वक़्त के आर्थिक मुश्किलों के लिए जनता ने ज़िम्मेदार नहीं ठहराया था.[1,2]



रीगन को हमेशा ग्रेट कम्यूनिकेटर माना जाता था और इस खासियत के चलते ही उनकी गलतियां कभी भी उनसे चिपकी नहीं. मोदी भी उसी राह पर नजर आते हैं.

कईयों का मानना है कि मोदी ने भारतीय चुनाव को अमरीका के प्रेसीडेंशियल इलेक्शन जैसा बना दिया है. लेकिन मजबूत प्रधानमंत्री भी अपनी पार्टियों से ऊपर नजर आते रहे हैं- मार्गेट थैचर, टोनी ब्लेयर और इंदिरा गांधी का उदाहरण सामने है.

डॉक्टर वैष्णव बताते हैं, "इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इस पर कोई सवाल नहीं है. मौजूदा समय में राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कोई चुनौती देने की स्थिति में भी नहीं है."

2014 में उनकी जीत की एक वजह भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की नाराजगी भी थी. लेकिन गुरुवार को जो जीत मिली है वह मोदी को स्वीकार किए जाने की जीत है. वे 1971 के बाद ऐसे पहले नेता बन गए हैं जिन्होंने लगातार दो बार अकेली पार्टी को बहुमत दिलाया है. अशोका यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर महेश रंगराजन कहते हैं, "यह मोदी और नए भारत को लेकर उनके विचार की जीत है." राष्ट्रवाद, धार्मिक धुवीकरण और जनकल्याण की कई योजनाओं के आपसी गठजोड़ ने नरेंद्र मोदी को लगातार दूसरी बार जीत दिलाई है.[3,4]



एक तरह से कटुता भरे और समाज को बांटने वाले चुनावी अभियान में मोदी ने राष्ट्रवाद और विकास के कॉकटेल को मुद्दा बनाया. उन्होंने समाज को दो वर्गों में पेश किया, एक वे जो उनके समर्थक हैं, वो राष्ट्रवादी हैं और जो उनके राजनीतिक विरोधी, आलोचक हैं उन्हें उन्होंने एंटी नेशनल कहा.

मोदी ने खुद को चौकीदार कहा, देश की ज़मीन, हवा और बाहरी अंतरिक्ष, सबकी सुरक्षा करने वाला बताया और जबकि मुख्य विपक्षी कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया.

इसके साथ उन्होंने विकास का वादा भी दोहराया. मोदी ने गरीबों को ध्यान में रखकर जनकल्याण योजनाएं शुरू कीं, जिनमें गरीबों के लिए मकान, शौचालय, क्रेडिट, और कुकिंग गैस की व्यवस्था शामिल थीं. तकनीक के इस्तेमाल से इसे जल्द लागू किया गया. हालांकि इन सुविधाओं की गुणवत्ता और यह गरीबी दूर करने में कितना कामयाब रहा, इसपर बहस संभव है. नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को भी जोर शोर से उछाला. हाल के चुनावों में इससे पहले ऐसा कभी नजर नहीं आया था. भारत प्रशासित कश्मीर में आत्मघाती चरमपंथी हमले में 40 पैरामिलिट्री जवानों की मौत हुई, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तानी सीमा में एयर स्ट्राइक किया. इसका भी चुनावी फायदा हुआ. मोदी आम लोगों को यह समझाने में कामयाब रहे कि अगर वे सत्ता में लौटते हैं तो देश सुरक्षित हाथों में रहेगा.[5,6]



आम लोगों की विदेश नीति में दिलचस्पी नहीं होती है। लेकिन चुनावी रिपोर्टिंग करने के दौरान हमें, किसानों, व्यापारियों और श्रमिकों ने यह माना कि मोदी के नेतृत्व में भारत का सम्मान विदेशों में बढ़ा है। कोलकाता में एक आम मतदाता ने कहा था, "ठीक है कि कम विकास हुआ है लेकिन मोदी जी देश को सुरक्षित रख रहे हैं और भारत का सिर ऊंचा किए हुए हैं।" मोदी की छवि उनकी कैडर आधारित पार्टी से बड़ी हो गई है। वे कईयों के लिए उम्मीद और आकांक्षाओं के प्रतीक बन गए हैं। मोदी और उनके बेहद विश्वस्त सहयोगी अमित शाह, ने मिलकर पार्टी को एक मशीन के रूप में तब्दील कर दिया है। महेश रंगराजन कहते हैं, "बीजेपी का जो भौगोलिक विस्तार हुआ है, वह बेहद अहम बदलाव है।" परंपरागत तौर पर बीजेपी को उत्तर भारत के हिंदी बोलने वाले राज्यों में व्यापक समर्थन मिलता रहा है (2014 में पार्टी ने जो 282 सीटें जीती थीं, उनमें 193 इन्हीं राज्यों में मिली थीं)। गुजरात और महाराष्ट्र अपवाद हैं।[7,8]

गुजरात मोदी का गृह प्रदेश और बीजेपी का गढ़ है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी ने स्थानीय पार्टी शिवसेना से गठबंधन किया हुआ है। जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से बीजेपी ने असम और त्रिपुरा में सरकार बनाई हैं जो प्राथमिक तौर पर असमिया और बंगाली बोलने वाले राज्य हैं। एनडीए का सामना मुख्यतः कांग्रेस व उसके गठबंधन वाली पार्टियों से था, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के नाम से एकजुट था। इसे महागठबंधन कहा जा रहा था और मोदी ने सीधे इसी पर प्रहार शुरू किए। अप्रैल 2019 में दादर नागर हवेली के सिलवासा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह महागठबंधन उनके खिलाफ नहीं, बल्कि राष्ट्र के खिलाफ लड़ रहा है। इस तरह मोदी है तो मुमकिन है के साथ उन्होंने खुद को राष्ट्र के समानांतर खड़ा कर लिया कि उनके विरोधी राष्ट्र विरोधी हो गए। अपनी विशिष्ट भाषण शैली में उन्होंने महागठबंधन को 'महाठगबंधन' का नया नाम भी दे दिया। मोदी का ये दाव खासा प्रभावकारी रहा।

मोदी को चुनौती दे रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव अभियान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। देश भर के दौरे कर 'चौकीदार चोर है' जैसे नारों के साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए, लेकिन खुद को नरेंद्र मोदी के विकल्प की तरह प्रस्तुत नहीं किया, न ही कांग्रेस जैसी राजनीति का लंबा इतिहास रखने वाली पार्टी में किसी ने उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि वे नरेंद्र मोदी पर हमले करने से बचें और इस चुनावी जंग को नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी बनाने की कोशिश न करें। इसके बजाय वे आमजन से जुड़े मुद्दे उठाए। उनकी समस्याओं की बात करें। इनमें स्थानीय मुद्दों तथा बीजेपी सरकार की असफलताओं का तड़का लगाएं। विपक्षी उम्मीदवार की कमजोरियों, असफलताओं की चर्चा करें। कांग्रेस की कार्य समिति में शामिल वरिष्ठ नेताओं ने भी उनकी आंख खोलने के प्रयास नहीं किए कि देश के गरीब से गरीब, पिछड़े तथा उच्च जाति वाले नागरिकों के बीच नरेंद्र मोदी की इमेज साफ-सुथरी है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं तथा इस तरह के हमलों से जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है।[9,10]

विचार – विमर्श

इस चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे. इतना नहीं बीजेपी ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी शक्तिशाली होकर उभरी है. हालांकि दक्षिण भारत में पार्टी की मौजूदगी भर है, लिहाजा अभी भी बीजेपी कांग्रेस की तरह अखिल भारतीय पार्टी नहीं बनी है. लेकिन बीजेपी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है.

बीस साल पहले जब बीजेपी, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सत्ता में आई थी तब गठबंधन की सरकार थी और बीजेपी के सामने सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर स्थिर सरकार चलाने की चुनौती भी थी. जबकि मोदी के नेतृत्व में बीजेपी खुद ही बहुमत में है. कोई भी मोदी और अमित शाह की हैसियत में नहीं हैं और वे आक्रामक अंदाज़ की राजनीति करते हैं. पार्टी का तंत्र केवल चुनावी मौसम में नजर आता हो, ऐसी बात नहीं है. पार्टी स्थायी तौर पर चुनावी अभियान में जुटी नजर आती है.

राजनीतिक वैज्ञानिक सुहास पलिष्कर का मानना है कि एक पार्टी के प्रभुत्व वाले दौर में देश तेजी से आगे बढ़ेगा, जैसे कांग्रेस के नेतृत्व में अतीत में हो चुका है. वे इसे पार्टी प्रभुत्व वाली व्यवस्था का दूसरा दौर बताते हैं, जिसमें बीजेपी का दबदबा है जबकि कांग्रेस कमजोर बनी हुई है और क्षेत्रीय दल अपना आधार खोते दिख रहे हैं. मोदी ने अपने चुनावी अभियान में राष्ट्रवाद को सबसे अहम मुद्दा बनाए रखा. इसके सामने मतदाता अपनी आर्थिक मुश्किलों को भी भूल गए.

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक विशिष्ट संस्कृति वाले लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है, इसके संरक्षण के लिए देश की बहुमत वाली आबादी को सक्रिय होने की ज़रूरत होगी.

समाजशास्त्री सैमी समहा के मुताबिक यह काफ़ी हद तक इसराइल जैसा होगा, जो अपनी यहूदी संस्कृति की पहचान के साथ साथ पश्चिमी यूरोप की प्रेरणा से संसदीय व्यवस्था को लागू किए हुए है.[11,12]

तो क्या हिंदू राष्ट्रवाद भारतीय राजनीति और समाज की पहचान बन जाएगी लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा- भारत में काफ़ी विविधताएं हैं. हिंदुत्व भी विविधता वाली आस्था है. सामाजिक और भाषाई स्तर पर विभिन्नताएं ने भी देश को आपस में जोड़कर रखा है. लोकतंत्र समाज को जोड़ने वाला एक और ग्लू है.

वैसे बीजेपी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को मिलाकर जिस हिंदू राष्ट्रवाद की बात करती है, वह सभी भारतीयों को प्रभावित करे, यह ज़रूरी नहीं है. प्रोफ़ेसर रंगराजन कहते हैं, "दुनिया में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां इतनी अधिक विविधता है और एकरूपता लाना मुश्किलों से भरा है."

भारत में दक्षिणपंथ को लेकर यह झूकाव कोई नहीं बात नहीं है- यह अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी के सत्ता में आने के साथ हो चुका है और फ्रांस और जर्मनी की राजनीति भी दक्षिणपंथ की ओर बढ़ रही है.

ऐसे में भारत का दक्षिणपंथी राजनीति की ओर झूकाव, एक विस्तृत टैंड का हिस्सा है जिसमें राष्ट्रवाद भी नए सिरे से परिभाषित हो रहा है और सांस्कृतिक पहचान को भी नए सिरे से तय किया जा रहा है.

ऐसे में मोदी के नेतृत्व में भारत बहुसंख्यक आबादी का राज बन जाएगा, यह डर कितना सही है?

मोदी ऐसे पहले नेता नहीं हैं जिन्हें आलोचक फासीवादी और सत्तावादी कह रहे हैं. इससे पहले इंदिरा गांधी को भी ऐसा कहा गया था. 1975 में उन्होंने देश में आपातकाल लागू किया था जिसके दो साल बाद ही आम लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था.

वैसे मोदी बेहद मजबूत नेता हैं और लोग उन्हें इसलिए पसंद करते हैं. 2017 में आयी सीएसडीएस की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2005 70 प्रतिशत लोकतंत्र को पसंद करते थे जो 2017 में 63 प्रतिशत रह गए थे. प्यू की 2017 की एक रिपोर्ट में भी 55 प्रतिशत भागीदारों ने कहा था कि ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें कोई भी मजबूत नेता, संसद और अदालत के दखल के बिना फ़ैसला ले सके.

मजबूत नेता की चाहत केवल भारत में नजर आ रही हो, ऐसा भी नहीं है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, तुर्की के राष्ट्रपति रेचैप तैय्यप आर्दाऑन, हंगरी के विक्टर ओर्बान, ब्राजील के जैर बोलसोनारो और फिलिपींस के रोड्रिगो दुतेर्ते भी इसी सूची में शामिल हैं.[13,14]

तब-तक मोदी की छवि ऐसे नेता की बन चुकी थी, जो दुश्मन, खासतौर से पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात करने की, या उसे अपनी 'औकात' दिखा देने की क्षमता रखता है. पुलवामा में आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय 'घर में घुस के मारा' के बयान ने उनकी छवि आगे से वार करने वाले नेता की बना दी थी. निश्चित ही इससे देशवासियों की एक बड़ी संख्या प्रभावित थी. इससे वे संतुष्टि व गर्व महसूस करते थे. ऐसे हालात में राहुल गांधी अगर इतिहास पर नज़र डालते तो उन्हें सन् 1971 का युद्ध याद आ जाता, जिसके माध्यम से इंदिरा गांधी बांग्लादेश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देकर राष्ट्र की सर्वमान्य नायिका का दर्जा प्राप्त कर चुकी थीं.

रफ़ाल करार को लेकर मोदी पर किए गए हमलों से भी राहुल की न सिर्फ़ किरकिरी हुई बल्कि उन्हें अदालत में माफ़ी भी मांगनी पड़ी. 'चौकीदार चोर है' के चक्कर में उनकी जुबान फिसल गई और वे इस नारे को सुप्रीम कोर्ट से जोड़ बैठे. तब उन पर अदालत की अवमानना का केस चला और राहुल के कानूनी सलाहकार उन्हें भरोसा देते रहे कि सब ठीक हो जाएगा. इस चक्कर में पांच

चरणों का मतदान तक हो गया. नतीजतन पूरे चुनाव में इस केस के प्रति लोगों की जिज्ञासा बनी रही. आखिरकार अदालत ने उनकी खबर ली और तुरंत ही टीवी स्क्रीन पर 'राहुल को पड़ी सुप्रीम कोर्ट की फटकार' जैसे नारे नज़र आने लगा. तब उन्हें न्यायालय से माफ़ी मांगनी पड़ी. जानकारों के मुताबिक अगर पहली सुनवाई में ही यह माफ़ी मांग ली गई होती तो बात का बतंगड़ न बनता. जबकि उनकी कानूनी टीम खेद जताने या माफ़ी मांगने जैसे शब्दों पर चिंतन-मनन में लगी रही.

सन् 2006 में हैदराबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया कि "हर राजनीतिक संगठन को ऐसे दूरदर्शी नेता की जरूरत होती है, जो वर्तमान की चुनौतियों का सामना करते हुए समाज की परंपरागत सोच को बदल दे." कांग्रेस के लिए और कड़वी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने यह काम कर दिखाया. उनमें वोटर्स को ऐसा नेता दिखा जो राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखता है. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने तीन तलाक को अवैध करार देने तथा कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने जैसे निर्णय लेकर अपने हिंदूवादी वोटर्स को आश्चर्य करने की कोशिश भी की कि मोदी के रूप में उन्होंने उचित चुनाव ही किया है.

इसके ठीक पांच साल पहले 16 मई 2014 में आम चुनावों के बाद मोदी ये करिश्मा पहले ही कर चुके थे. उस दिन कई रिकॉर्ड टूटे. बीजेपी ने तब इतिहास रचते हुए लोकसभा की 282 सीटों पर विजय हासिल की थी, जो 1998-1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लाई गई 182 सीटों से पूरी सौ सीटें ज्यादा थीं. 1984 के बाद यह पहला मौका था, जब किसी पार्टी ने अकेले सदन की आधी से ज्यादा सीटें जीत ली थीं. इससे गठबंधन सरकारों का सिलसिला समाप्त हो गया, हालांकि, मोदी ने अपने गठबंधन की पार्टियों को सरकार में शामिल भी किया था.[15,16]

साल 2014 के इस चुनाव में कांग्रेस को करारी मात मिली और पार्टी मात्र 44 सीटों पर सिमट गई. 1951-52 के बाद यह उसका ऐतिहासिक निम्नस्तर था. मोदी की सेना ने 128 साल पुरानी पार्टी का सफाया कर दिया था. 'अब की बार मोदी सरकार' वाला चुनाव अभियान वाकई बेहद प्रभावशाली था और इस चुनाव अभियान ने कई मामलों में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा सन् 2008 में चलाए गए चुनाव अभियान को पीछे छोड़ दिया था.

देश की सत्ता हासिल कर लेने के बाद मोदी ने अपने विश्वस्त साथी अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा लिया. बायो-केमेस्ट्री में स्नातक अमित शाह के साथ विवादों की छाया लगी हुई है, परंतु वे गुजरात के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति के कुशल खिलाड़ी साबित हुए. अगले तीन सालों में मोदी-शाह की जोड़ी ने दिल्ली और बिहार को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों में अपनी पार्टी की सत्ता स्थापित कर ली.

परिणाम

कांग्रेस को लगातार दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा. हालांकि राष्ट्रीय तौर पर वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है. लेकिन वह बीजेपी से काफ़ी पिछड़ चुकी है और सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है. उसका मौगोलिक दायरा भी सिमटता जा रहा है.

देश की सबसे घनी आबादी वाले राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल में कांग्रेस का अस्तित्व लगभग नहीं के बराबर है. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में पार्टी नजर नहीं आती. औद्योगिक तौर पर विकसित गुजरात में कांग्रेस ने आखिरी बार 1990 में चुनाव जीता था. जबकि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय से ही पार्टी महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर है.

लगातार दूसरे आम चुनाव में हार के बाद कई सवाल हैं, जो पूछे जा रहे हैं. पार्टी अपने सहयोगियों के बीच ज्यादा स्वीकार्य कैसे होगी? पार्टी कैसे चलेगी? पार्टी गांधी परिवार पर अपनी निर्भरता को कैसे कम करेगी? पार्टी अपने युवा नेताओं को कैसे मौका देगी? अभी भी कई राज्यों में कांग्रेस दूसरी और तीसरी पीढ़ी के नेताओं की पार्टी बनी हुई है. बीजेपी का सामना करने के लिए कांग्रेस ज़मीनी कार्यकर्ताओं का नेटवर्क कैसे तैयार करेगी?

मिलान वैष्णव कहते हैं, "कांग्रेस अव्यवस्थित रहेगी, जैसे बीते कई चुनावों में देखने को मिला है. कांग्रेस की पहचान आत्म विश्लेषण करने वाली पार्टी की नहीं रही है. लेकिन भारत में दो दलीय व्यवस्था के चलते मुश्किलों के बावजूद कांग्रेस की जगह बची रहेगी."

राजनीति वैज्ञानिक और इन दिनों राजनीति में सक्रिय योगेंद्र यादव का मानना है कि कांग्रेस की उपयोगिता खत्म हो चुकी है और इसे खत्म हो जाना चाहिए. लेकिन राजनीतिक दल खुद में बदलाव लाकर वापसी करने में सक्षम होते हैं. ऐसे में इसका पता तो भविष्य में ही लगेगा कि क्या कांग्रेस नए सिरे से वापसी कर पाएगी या नहीं? मोदी-शाह की जोड़ी 1982 के दिनों की याद दिला देती है. जब मोदी अहमदाबाद (गुजरात) के मणिनगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक व युवा क्रियाकलाप प्रमुख थे. शाह तब संघ के कार्यकर्ता थे. मोदी ने शाह की प्रतिभा को पहचाना और सन् 2001 में जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, तब उन्होंने शाह को अपने मंत्रिमंडल में गृह, संसदीय कार्य, विधि, आबकारी तथा परिवहन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए. मोदी और शाह की इस जोड़ी ने गुजरात में ज़मीनी स्तर पर काम किया. खासतौर से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कांग्रेसी नेताओं पर मेहनत की जो खुद को पार्टी में उपेक्षित महसूस करते थे. उन्हें अपने साथ मिलाकर एक नई ताकत तैयार कर ली गई. गुजरात के प्रभावशाली को-ऑपरेटिव आंदोलन को भी इसी तरह की रणनीति से अपने पाले में कर लिया गया. भारत के चुनावी इतिहास में यह पहला मौका नहीं था जब किसी पार्टी को लोकसभा में ऐसा भारी बहुमत मिला हो. 10 साल से कांग्रेस की गठबंधन सरकार

सत्ता में थी. बीजेपी लगातार दो लोकसभा चुनाव, पहला अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरा लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हार चुकी थी. उसके बाद 2014 में मिली एक बंपर जीत नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व व उनकी आक्रामक राजनीतिक शैली की ही देन थी.[17,18]

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार सन् 2011 से ही मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया था. हालांकि, यह बहुत स्पष्ट रूप से नहीं था, लेकिन अपरोक्ष रूप से पार्टी के भीतर भी यही हवा बनाई गई कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के सबसे उपयुक्त उम्मीदवार वही हो सकते हैं. यह काम किस स्तर पर किया होगा, इसका अंदाज़ा भाजपा संसदीय दल की बैठक (13 सितं 2013) से लगाया जा सकता है, जिसमें यह निर्णय लिया गया था. 20 दिसंबर 2012 को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आए. नरेंद्र मोदी चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे. 13 सितंबर 2013 भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक हुई. इसमें नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित कर दिए गए. इस सब से पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी खुश नहीं थे, इसलिए वे इस बैठक में शरीक नहीं हुए. वे मोदी के नाम का विरोध इस आधार पर कर रहे थे कि इससे यूपीए सरकार के खिलाफ सतत उठाए जा रहे महंगाई व बेरोज़गारी जैसे मुद्दे गौण हो जाएंगे. मगर मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने को लेकर तब तक कितना काम हो चुका था, यह इसी से समझा जा सकता है कि तब आडवाणी के साथ पार्टी के बहुत कम लोग थे. मात्र मुरली मनोहर जोशी व सुषमा स्वराज उनसे सहमत थे. बाकी पूरी जमात नरेंद्र मोदी के साथ थी, जिससे ये साबित हुआ कि मोदी पार्टी के भीतर अपनी पहली जंग बिना लड़े ही जीत चुके थे.

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जो किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले संसद में सबसे अधिक सांसद भेजता है. बीजेपी ने यहां 2014 के अपने प्रदर्शन को दोहराया है जब उसने 80 सीटों में से 71 सीटों पर विजय हासिल की थी. इस बार उसे 62 और उसके सहयोगी पार्टी को दो सीटें मिली हैं.

ये भारत के सबसे अधिक सामाजिक रूप से बंटे और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में एक है.

इस बार उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के महागठबंधन की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मोदी के करिश्मे और कैमैस्ट्री के सामने दोनों राजनीतिक दलों का सामाजिक गणित नाकाम साबित हुआ. पहले यह माना जाता था कि इन दोनों पार्टियों का अपना कोर वोट बैंक है, लेकिन यह भरोसा टूट गया है. यह साबित भी हो गया है कि जाति आधारित गणित को तोड़ा जा सकता है.

भारत के क्षेत्रीय दलों को अपनी रणनीति पर विचार करना होगा और उन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण पर काम करना होगा. नहीं तो उनके अपने मतदाता भी उनका साथ छोड़ते जाएंगे.

मोदी आक्रामक शैली में राजनीति करने वाले राजनेता हैं. हालांकि, उनका इस आक्रामकता की सफलता का राज़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज़मीनी कार्य में छिपा है, इसीलिए वे संघ के प्रति सदैव नतमस्तक नज़र आते हैं. उनके राजनैतिक विरोधियों के अनुसार मोदी आत्ममुग्ध भी हैं. साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कभी-कभार ही महत्वपूर्ण विदेश दौरों पर गईं. पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिना रुके पूरी दुनिया नाप डाली. अपनी मार्केटिंग के प्रति सदैव सजग रहने वाले मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद प्रचार किया गया कि वे 18 से 20 घंटे काम करते हैं. भारतीय प्रधानमंत्री के लिए यह सामान्य बात है. इंदिरा गांधी अक्सर 20 घंटे तक काम करती थीं. इधर मोदी अनथक काम करने के प्रचार की आड़ में फौरन विदेश दौरे पर निकल जाते. तब उनके आलोचक हाथ मलते हुए पीछे से कहते कि प्रधानमंत्री कभी अपना घर यानी देश भी देख लिया करें. या यह कि वे तो मात्र हाज़िरी लगाने के लिए भारत आते हैं. इन निरंतर चलने वाली विदेश यात्राओं के कारण उनके कटु आलोचकों ने उन्हें लापरवाह किस्म का प्रधानमंत्री कहना शुरू कर दिया था. उनकी नज़र में प्रधानमंत्री विदेश यात्राओं पर ख़ासा खर्च करने के साथ अपनी वेशभूषा व रंग-रूप को लेकर भी आत्ममुग्ध से हैं, जो तरह-तरह के और ख़ासे महंगे परिधान पहनने के शौकीन हैं. इस बाबत प्रधानमंत्री द्वारा एक आयोजन के अवसर पर पहना गया दस लाख रुपए वाले सूट की ख़ूब चर्चा हुई. इस सूट में सोने की कारीगरी से प्रधानमंत्री का नाम लिखा हुआ था.

एक कट्टर हिंदूवादी नेता की अपनी छवि बरकरार रखने के लिए नरेंद्र मोदी ने हमेशा सार्वजनिक मंच पर टोपी पहनने से इंकार किया. वे अच्छी तरह जानते थे कि उनके कट्टर हिंदूवादी वोटर्स को यह बात बहुत पसंद नहीं आएगी. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार अपने इसी वोटर को जोड़े रखने के लिए ही मोदी सरकार ने तीन तलाक को कानूनी तौर पर अवैध साबित करने और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करने जैसे फैसले लिए. उनकी इसी छवि को देखते हुए समझा जा सकता है कि नागरिकता संशोधन एक्ट और एनपीआर व एनआरसी जैसे क़ानूनों में उनकी दिलचस्पी कितनी होगी.[19]

मोदी ने आरएसएस व संघ परिवार में अपने आप को दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा से जोड़ा लेकिन वरिष्ठ संपादक व लेखिका मानिनी चटर्जी के अनुसार आरएसएस को मोदी के रूप में एक ऐसा नेता मिल गया है जो भगवा ध्वज का सपना साकार कर सकता



है. लेकिन अधिकांश राजनैतिक विश्लेषकों का मानना है की भारतीय लोकतंत्र की मर्यादा व संविधान के स्वरूप को क्रायम रखने में मोदी उनसे पहले बने 13 प्रधान मन्त्रियों से कम नहीं बल्कि बढ़कर योगदान देंगे.[20,21]

संदर्भ

1. "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल से 13 अप्रैल 2014 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 11 अप्रैल 2014.
2. ↑ "राष्ट्रपति ने श्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया". पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार. 20मई 2014. मूल से 21 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 मई 2014. |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
3. ↑ "Narendra Modi appointed Prime Minister, swearing in on May 26". Times of India. 20 मई 2014. मूल से 2 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 21 मई 2014.
4. ↑ "PM Modi turns 69: A timeline of his political career". Deccan Herald (अंग्रेज़ी में). 2019-09-17. मूल से 15 जनवरी 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-20.
5. ↑ "Live Latest News Headlines at newkerala.com Daily News". www.newkerala.com. मूल से 2014-03-15 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-20.
6. ↑ Marino, Andy (2014-04-06). Narendra Modi: A political Biography (अंग्रेज़ी में). Harper Collins. पृ॰ 24. आई॰एस॰बी॰एन॰ 978-93-5136-218-0.
7. ↑ Shekhar, Himanshu (1901). Management Guru Narendra Modi (अंग्रेज़ी में). Diamond Pocket Books Pvt Ltd. पृ॰ 64. आई॰एस॰बी॰एन॰ 978-81-288-2803-4.
8. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 4 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2018.
9. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 20 दिसंबर 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2018.
10. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 मार्च 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 मई 2018.
11. ↑ "गूगल सर्च में भी नरेंद्र मोदी पड़े राहुल गांधी पर भारी". दैनिक जागरण. मूल से 9 अक्टूबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 9 अक्टूबर 2013.
12. ↑ "Vote Now: Who Should Be TIME's Person of the Year?". टाइम. मूल से 28 नवंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 27 नवम्बर 2013. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (मदद)
13. ↑ "नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद की रैली में सुनाई कविता". नवभारतटाइम्स.कॉम. 20 फ़रवरी 2014. मूल से 12 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 मई 2014.
14. ↑ "कविता के जरिए नरेंद्र मोदी ने बयां किया दर्द-ए-दिल". आज तक. 27 अप्रैल 2014. मूल से 12 मई 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 मई 2014.
15. ↑ "Partywise Trends & Result". मूल से 23 फ़रवरी 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 मई 2014.
16. ↑ "नरेन्द्र मोदी वाराणसी से चुनाव लडेगे". देशबन्धु. 15 मार्च 2014. मूल से 17 मार्च 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 मार्च 2104. |accessdate= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)
17. ↑ "गुजरात से चुनाव लडेगे नरेन्द्र मोदी". बीबीसी हिन्दी. 13 मार्च 2014. मूल से 17 अप्रैल 2014 को पुरालेखित.
18. ↑ Stepan, Alfred (2015-01-07). "India, Sri Lanka, and the Majoritarian Danger". Journal of Democracy (अंग्रेज़ी में). **26** (1): 128–140. आई॰एस॰एस॰एन॰ 1086-3214. डीओआइ:10.1353/jod.2015.0006.
19. ↑ "NITI Aayog Releases State Statistics Handbook | ABC Live India" (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2021-01-21.
20. ↑ "Alliance Wise Election Live Results 2019: Lok Sabha Elections Result Live Alliance Wise, Party Wise". News18. मूल से 12 नवंबर 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-21.
21. ↑ "PM Modi Becomes Longest Serving Non-Congress Prime Minister". NDTV.com. मूल से 18 दिसंबर 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2021-01-21.



**Impact Factor:
7.569**



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details